

मूक पत्रिका

निष्पक्ष, निर्भीक, स्वतंत्र आवाज...

वर्ष – 02 अंक – 238 बेमेतरा, गुरुवार 23 अप्रैल 2026 रायपुर एवं बेमेतरा से प्रकाशित कुल पेज – 08 मूल्य – 5 रूपये डाक पंजीयन- दुर्ग/1743290201/2025-27

संक्षिप्त समाचार

पहले चरण में कुल 152 सीटों पर मतदान

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को 152 सीटों पर पहले चरण का मतदान होगा। इसके तहत राज्य में 16 जिलों में से 7 जिलों को सुरक्षा की दृष्टि से सबसे संवेदनशील माना गया है। चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाते हुए इन जिलों में केंद्रीय बलों के साथ 2193 क्रिक रिस्पांस टीम तैनात कर सुरक्षा का मजबूत घेरा बनाया है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग 23 अप्रैल को होने जा रही है, जिसमें कुल 152 सीटों पर मतदान होगा। यह सीटें राज्य के 16 जिलों में फैली हुई हैं। मतदान से पहले इन जिलों को लेकर चुनाव आयोग ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। इसके तहत राज्य में 16 जिलों में से 7 जिलों को सुरक्षा की दृष्टि से सबसे संवेदनशील माना गया है। इनमें मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, कूच बिहार, बीरभूम, पश्चिम मिदनापुर और पश्चिम बर्दवान शामिल हैं। इन जिलों में पिछले 15 वर्षों के चुनावी हिंसा के रिकॉर्ड और संवेदनशील व्यूथों के आधार पर निगरानी बढ़ा दी गई है। हालात के गंभीरता को देखते हुए चुनाव आयोग ने इन क्षेत्रों में केंद्रीय सुरक्षा बलों की भारी तैनाती का आदेश दिया है।

कलयुगी पिता ने नाबालिग बेटी का गला घोट चेहरे पर डाला तेजाब

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से रिश्तों की शर्मसार कर देने वाली एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक पिता ने प्रेम प्रसंग के शक में अपनी ही नाबालिग बेटी को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद हैवान बने पिता ने बेटी की पहचान मिटाने के लिए उसके चेहरे पर तेजाब डाल दिया और शव को बाराबंकी की शारदा नहर में फेंक दिया। चिनहट थाना क्षेत्र से जुड़े इस खौफनाक हत्याकांड के खुलासे ने हर किसी को सन्न कर दिया है। इस सनसनीखेज मामले में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह रही कि कातिल पिता ने हत्या के बाद पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश की। आरोपी पिता ने खुद 16 अप्रैल को चिनहट थाने पहुंचकर अपनी बेटी के रहस्यमय तरीके से गायब होने की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। लेकिन, पुलिस जांच के दौरान जब कड़ियां जुड़ने लगीं, तो पिता के बयानों में विरोधाभास नजर आया। पुलिस का शक गहराने पर जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई, तो वह टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया।

विमान में आई तकनीकी खराबी से मचा हड़कंप

नई दिल्ली। हैदराबाद से हुबली की उड़ान भर रहे फ्लाइट91 एयरलाइंस के एक विमान में सवार यात्रियों के लिए किसी बुरे सपने जैसा रहा। तकनीकी खराबी की वजह से फ्लाइट करीब चार घंटे तक आसमान में ही गोते खा रही, जिससे विमान के अंदर चीख-पुकार और दहशत का माहौल पैदा हो गया। चालक दल की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया और विमान को सुरक्षित उतार लिया गया।

बंगाल में अपना खाता भी नहीं खोल पाएगी कांग्रेस

ममता दीदी की विदाई की तिथि 4 मई-अमित शाह...

नई दिल्ली/ एजेंसी

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दम दम उत्तर विधानसभा में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और टीएमसी पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस दोनों पर बरसे। शाह ने दावा किया कि इस बार बंगाल से ममता दीदी की विदाई हो जाएगी। अमित शाह ने इस दौरान पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। साथ ही मल्लिकार्जुन खरगे को पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर भी घेरा। अमित शाह ने कहा, 4 मई को सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। 9 बजे पहला राउंड आएगा, दोपहर 1 बजे तक गिनती समाप्त होते-होते ममता दीदी का टाटा-बाय-बाय हो जाएगा। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के पीएम मोदी पर दिए बयान पर पलटवार किया है। अमित शाह ने कहा कि खरगे पहले इस तरह के बयान नहीं देते थे। लेकिन, राहुल बाबा के साथ रह कर उनकी भाषा भी बिगड़ने लगी है। राहुल के साथ रहने का ही असर है जो कांग्रेस अध्यक्ष पीएम नरेंद्र मोदी जी को आतंकवादी कह रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आज दम दम उत्तर विधानसभा में जनसभा की। अमित शाह ने कहा, 4 मई को सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। 9 बजे पहला राउंड आएगा, 10 बजे दूसरा राउंड आएगा, और दोपहर 1 बजे तक गिनती समाप्त होते-होते ममता दीदी का टाटा-बाय-बाय हो जाएगा। 29 तारीख को आप सभी को वोट डालना है, लेकिन किसी को विधायक या भाषया बकारा बनाने के लिए नहीं, बल्कि घुसपैठिया मुक्त बंगाल बनाने के लिए वोट डालना है नरेंद्र मोदी जी को कांग्रेस अध्यक्ष आतंकवादी कह रहे हैं। राहुल बाबा के साथ रह रह कर खरगे जी की भी भाषा बिगड़ने लगी है। राहुल बाबा, मोदी जी जितना गाली दोगे, जितना कीचड़ गिराओगे, कमल उतनी शान से



बंगाल की पहचान से नहीं होगा खिलवाड़- योगी आदित्यनाथ

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए भाजपा के प्रचार अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जोरपासांको विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और पार्टी उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार किया। सभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोलकाता के मेयर के बयान सामने आ रहे हैं, जिसमें उर्दू के इस्तेमाल की बात कही जा रही है। उन्होंने कहा कि बंगाल की पहचान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। बंगाल की पहचान काबा से नहीं, बल्कि मां कालीबाड़ी से जुड़ी रही है। उन्होंने राज्य में कानून-व्यवस्था और अन्य मुद्दों पर भी सवाल उठाए। योगी ने कहा कि बंगाल में अव्यवस्था का माहौल वैसा ही है जैसा 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में था। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए कहा कि अब वहां शांति और विकास का माहौल है।



खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को निर्वाचन आयोग पहुंचा और उसने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की आतंकवादी संबंधी टिप्पणी के लिए उनके (खरगे) खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस प्रतिनिधिमंडल में निर्मला सीतारमण समेत तीन केंद्रीय मंत्री शामिल थे। निर्मला सीतारमण ने कहा कि चुनावी राज्य तमिलनाडु में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए खरगे ने प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहा जो

अत्यंत निंदनीय है। सीतारमण ने कहा, यह भारत की जनता द्वारा दिए गए (प्रधानमंत्री मोदी को) जनतादेश का अपमान है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस पूरी तरह से हताश है और तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के बीच प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह की टिप्पणियां इसलिए कर रही हैं क्योंकि वह मोदी से गहरी नफरत करती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के दमदम में एक चुनावी रैली के दौरान कांग्रेस पर तीखा हमला बोला।

2500 करोड़ का बड़ा साइबर फाड़, 85 फर्जी खातों का खुलासा

नई दिल्ली। गुजरात के राजकोट में 2500 करोड़ रुपये के बड़े साइबर फॉड का खुलासा हुआ है। इस मामले में निजी बैंकों के अधिकारियों की सलाहता सामने आने के बाद पुलिस ने तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही कुल गिरफ्तार आरोपियों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। राजकोट (ग्रामीण) के पुलिस अधीक्षक विजय गुर्जर के अनुसार, पाधाधरी स्थित यस बैंक के पर्सनल मैनेजर मौलिक कामानी, जामनगर स्थित एक्सिस बैंक के मैनेजर कल्पेश डांगरिया और एचडीएफसी बैंक के पर्सनल बैंकर अनुराग बाल्था को गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया है कि मौलिक कामानी ने पहले से गिरफ्तार आरोपियों की मदद करते हुए संदिग्ध बैंक खाते खुलाए।

प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया

तीन मंजिला इमारत से गिरकर युवक की मौत, युवती की गंभीर

बिलासपुर। संवाददाता

बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र स्थित अभिलाषा परिसर की श्रद्धा बिल्डिंग में बुधवार को एक दर्दनाक घटना हुई, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। यहां तीन मंजिला इमारत की छत से एक युवक और युवती नीचे गिर गए, जिसमें युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि युवती गंभीर रूप से घायल हो गई है। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने दोनों को देखा और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से युवती को तत्काल सिम्स अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। डॉक्टरों की टीम उनका इलाज



कर रही है। युवक को भी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था और वे एक-दूसरे को जानते थे। घटना के पीछे क्या कारण रहा, इसको लेकर कई तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं।

नासा के हबल टेलीस्कोप ने कैद की ट्राइफिड नेबुला की शानदार तस्वीर

नई दिल्ली। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने तारों के निर्माण वाले क्षेत्र ट्राइफिड नेबुला की एक आकर्षक नई तस्वीर जारी की है। यह तस्वीर हबल के लॉन्च की 36वीं वर्षगांठ (24 अप्रैल) के मौके पर सामने आई है। पृथ्वी से करीब 5 हजार प्रकाश वर्ष दूर स्थित यह नेबुला तारों के बनने और गैस-धूल को आकार देने का अद्भुत नजारा पेश करता है। यह नई तस्वीर न केवल देखने में आकर्षक है, बल्कि यह ब्रम्हांड में हो रही जटिल प्रक्रियाओं को समझने में भी अहम भूमिका निभाती है।

कोर्ट ने भी राहत देने से किया इनकार

जबरन धर्मांतरण में शामिल थी निदा खान

मुंबई। मुंबई के नासिक स्थित टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेजमें यौन उत्पीड़न मामले में कंपनी की प्रोसेस एसोसिएट आरोपी निदा खान अब तक फरार है। कोर्ट ने निदा खान की अग्रिम जमानत पर सुनवाई 27 अप्रैल तक टाल दी है। क्योंकि अभी उन्हें कोई राहत नहीं मिली है, इसलिए पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। निदा खान ने अपनी दो महीने की प्रेनेंसी का हवाला देकर गिरफ्तारी से बचाव की मांग की थी अब अदालत 27 अप्रैल को अग्रिम जमानत याचिका और अंतरिम राहत याचिका दोनों पर



सुनवाई करेगी। पुलिस ने दावा किया है कि वह जबरन धर्मांतरण में शामिल थी। सेशंस कोर्ट से गिरफ्तारी पर अंतरिम सुरक्षा नहीं मिलने के बाद पुलिस ने कहा है कि निदा खान की तलाश जारी है।

अब खेलों से चमकेगा बस्तर

सचिन तेंदुलकर ने कहा बस्तर में प्रतिभा की कोई कमी नहीं

रायपुर/ एजेंसी



दत्तेवाड़ा के इंद्रावती किनारे बसे छिंदनार गांव ने उस पल इतिहास रच दिया, जब क्रिकेट जगत के महानायक सचिन तेंदुलकर अपने परिवार संग यहां पहुंचे। छिंदनार का खेल मैदान सचिन, सचिन. के नारों से गूंज उठा। इस दौरान बच्चों की आंखों में नए सपनों की चमक दिखाई दी। सचिन के साथ उनकी बेटी सारा तेंदुलकर, परिवार के सदस्य और मानदेशी फंडेशन की संस्थापक चेतना सिन्हा भी मौजूद रहीं। कार्यक्रम की शुरुआत खेल

का दिल जीत लिया। क्रिकेट के भगवान बच्चों संग बॉलीबॉल खेलते नजर आए। पूरे जोश के साथ खेल का आनंद लिया। इसके बाद सचिन ने मैदान का निरीक्षण किया और उन लोगों को सम्मानित किया, जिन्होंने इस खेल परिसर को तैयार करने में योगदान दिया। दत्तेवाड़ा जिले में अब तक 25 खेल मैदान तैयार हो चुके हैं, जबकि 25 और मैदानों की योजना पर काम जारी है। मंच से सचिन ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि यह सप्तर 50 मैदानों पर नहीं रुकेगा बल्कि 100 से अधिक मैदानों तक पहुंचेगा।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर विपक्ष के खिलाफ लाया जाएगा निंदा प्रस्ताव

30 अप्रैल को छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र आहुत

कांग्रेस ने सत्र के औचित्य पर उठाए सवाल रायपुर। संवाददाता

नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लोकसभा से पारित नहीं हो पाने पर 30 अप्रैल को छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र आहुत किया जा रहा है। सत्र के दौरान अधिनियम के पारित नहीं होने पर विपक्ष के खिलाफनिंदा प्रस्ताव लाया जाएगा। विधानसभा के विशेष सत्र की जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि सरकार की ओर से 30 अप्रैल को विशेष सत्र आयोजित करने का आग्रह हुआ। विधानसभा अध्यक्ष तय करेंगे कि कितने दिन का सत्र होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और विपक्षी दलों ने आधी आबादी को उनके

संवैधानिक अधिकार से वंचित करने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया है कि उनके अधिकार दिलाने तक संघर्ष जारी रहेगा। वहीं उप मुख्यमंत्री साव ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकवादी कहे जाने पर कहा कि कांग्रेस घटिया और निम्न स्तर की राजनीति कर रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस तरह की भाषा का उपयोग करना दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के देश में आतंकवाद, अलगाववाद और नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी और आतंकियों को मुंहतोड़



जवाब दिया। ऐसे प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कांग्रेस राजनीतिक पतन और घटियापन का दर्शाता है। सचिन तेंदुलकर के बस्तर दौरे को लेकर कांग्रेस द्वारा उठाए गए सुरक्षा सवालों पर अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि नक्सलवाद खत्म हो. नक्सली कांग्रेस के पाले-पोसे लोग रहे, इसलिए वे नहीं चाहते थे कि

बस्तर में शांति स्थापित हो. क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर बस्तर के युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इस पर भी राजनीति कर रही है। आदिवासी समाज के धर्मांतरण करने वालों की डी-लिस्टिंग की मांग पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि धर्मांतरण प्रदेश के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है

शिव डहरिया ने संभाला कांग्रेस का मोर्चा

वहीं विधानसभा के विशेष सत्र पर पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि इस तरह का कोई प्रावधान प्रजातंत्र में नहीं है. अगर है तो विपक्ष को भी एक दिन का मौका दें. उनकी पोल खोलकर रखेंगे. किस तरह से प्रजातंत्र का मखौल उड़ाया है. महिलाओं के अधिकारों को खत्म करने का काम मोदी सरकार कर रही है. उन सबके बारे में बताया जाएगा. जो बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया है, उसे लागू करना चाहिए. 2028 और 2029 के चुनाव में उसे लागू करना चाहिए. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपमान के सवाल पर शिव डहरिया ने कहा कि लोकतंत्र का अपमान तो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं. कांग्रेस पार्टी हमेशा लोगों का सम्मान करती है. अरुण साव नरेंद्र मोदी के लिए टिप्पणी कर रहे होंगे. प्रजातंत्र को नुकसान पहुंचाने का सबसे बड़ा काम हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं. हकीकत यह है कि नक्सली मुवमेट खत्म नहीं हुआ है, इसलिए डर में मुख्यमंत्री नहीं जा रहे हैं. सुरक्षा कारणों से सचिन के दौरे में कटौती की गई है. ऐसी जानकारी मिली है कि यह नक्सल मुवमेट को देखते हुए किया गया है. इससे सरकार के कार्यों पर प्रश्नचिह्न लगाता है. वहीं मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर को लेकर पूर्व मंत्री ने कहा कि बीजेपी की सरकार झूठी सरकार है. लगाता है मुख्यमंत्री दिल्ली के कटौल में चल रहे हैं. जनदर्शन लगाया करते थे उसके लाखों आवेदन पेंडिंग हैं. उसका निराकरण आज तक नहीं हो पाया है. हेल्पलाइन से कोई फ्रॉप पड़ने वाला नहीं है. दिखावे की राजनीति बीजेपी करती है. जनता की समस्याओं का निराकरण नहीं हो रहा है, इसलिए बरगलाने का काम सरकार कर रही है.



कलेक्टर ने फ़सल विविधीकरण, आगामी वर्ष की रणनीति एवं कृषि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा

कालाबाजारी पर सख्ती, किसानों को लाभकारी फ़सलों की ओर प्रेरित करने के निर्देश

जांजगीर चांपा/मूक पत्रिका

कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य सहित संबंधित विभागों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कृषि विभाग की समीक्षा करते हुए आगामी खरीफ सीजन में किसानों को समय पर और पर्याप्त मात्रा में खाद-बीज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी सहकारी समितियों में यूरिया एवं डीएपी का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसानों को किसी प्रकार की कमी का सामना न करना पड़े। उन्होंने खाद एवं बीज की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए गए। अधिकारियों को नियमित जांच कर अमानक सामग्री की बिक्री पर रोक लगाने एवं कार्रवाई करने के



लिए कहा गया। उन्होंने किसानों को कम पानी वाली फसलों और अधिक लाभदायक फसल विविधीकरण को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि खाद की कालाबाजारी, अवैध भंडारण एवं नकली खाद बेचने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने फॉर्मर आईडी बनाने, एग्रीस्टेक में पंजीयन कराने एवं किसानों को ई-केवाईसी पूर्ण कराने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने

अधिकारियों को कहा कि अधिक से अधिक किसानों को अभियान से जोड़कर सभी प्रक्रियाएं समय पर पूरी कराई जाएं, ताकि शासकीय योजनाओं का लाभ सीधे किसानों तक पहुंच सके। कलेक्टर ने उद्यानिकी विभाग की समीक्षा करते हुए फल, सब्जी एवं बागवानी फसलों के रकबे में वृद्धि करने और किसानों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ने के निर्देश दिए। बैठक में ड्रिप एवं

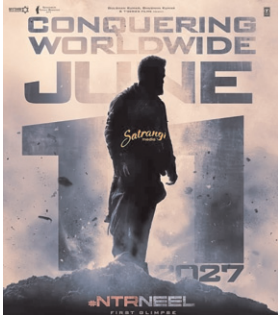
स्प्रिंकलर सिंचाई, पॉलीहाउस एवं शेडनेट जैसी योजनाओं का अधिकतम लाभ किसानों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। साथ ही, किसानों को उद्यानिकी फसलों की ओर प्रोत्साहित करने, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने और योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। बैठक में पशुधन विकास विभाग की समीक्षा करते हुए पशुधन संवर्धन कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए।बैठक में पशु चिकित्सा सेवाओं

को मजबूत करने, ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने तथा शतप्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि पशुपालकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं और विभागीय योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि पशुधन विकास को गति मिल सके। कलेक्टर ने सड़कों पर आवारा मवेशियों को हटाने संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने कहा कि दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए सड़कों से मवेशियों को हटाने एवं सुरक्षित स्थानों पर रखा जाए। कलेक्टर ने मत्स्य विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए मछली उत्पादन बढ़ाने और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन करने कहा। उन्होंने तालाबों के अधिकतम उपयोग, मत्स्य बीज की समय पर उपलब्धता और योजनाओं के पालन को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। बैठक में मछली पालकों को शसकीय योजनाओं का लाभ पहुंचाने, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने तथा आजीविका संवर्धन पर विशेष ध्यान देने कहा।

जित मुखर्ई/मूक पत्रिका

#NTRNeel 2027 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक होने वाली है। मनोरंजन की दुनिया की दो बड़ी ताकतें 'मैन ऑफ द मासेज' जूनियर एनटीआर और 'चतुर्ब' व 'सालार' के डायरेक्टर प्रशांत नील जब एक साथ आ रहे हैं, तो यह तय है कि दर्शकों को पर्दे पर एक अनोखा और भव्य सिनेमाई अनुभव देखने को पड़े पर एक अनोखा और भव्य सिनेमाई अनुभव देखने को मिलेगा!जब से सहस्रत्रहहृदय का ऐलान हुआ है, यह सबसे चर्चित फिल्मों में से एक बनी हुई है। भारतीय सिनेमा की दो सबसे बड़ी ताकतों, जूनियर एनटीआर और प्रशांत नील का साथ आना ही इसे 2027 की सबसे बड़ी फिल्मों की कतार में खड़ा कर देता है। बढ़ते उत्साह के बीच, मेकर्स ने एक बेहद रोमांचक पोस्टर जारी किया है और फिल्म की पहली झलक है और फिल्म की पहली झलक है। उनके इस नए लुक की तस्वीरें एनटीआर के जन्मदिन पर 20 मई को रिलीज होगी। पोस्टर में एनटीआर का



स्टाइल और पावरफुल अवतार फिल्म को लेकर बनी चर्चा को और भी बढ़ा रहा है। 20 मई को आने वाली पहली झलक के साथ फिल्म का क्रेज सातवें आसमान पर पहुंच गया है। एनटीआर के जन्मदिन के मौके पर रिलीज होने वाली यह झलक उन लाखों फैंस के लिए एक खास तोहफा होगी जो उन्हें बड़े पर्दे पर देखने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं?इसके अलावा, इस फिल्म के लिए एनटीआर के जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन ने सबको हैरान कर दिया है। उनके इस नए लुक की तस्वीरें पहले ही वायरल हो चुकी हैं और फैंस के बीच तल्लका मचा रही है। उन्हें इस

तरह के लुक में पहले कभी नहीं देखा गया, जिसने दर्शकों की उत्सुकता को और बढ़ा दिया है। सहस्रत्रहहृदय को प्रशांत नील की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी फिल्म बताया जा रहा है, जो एक शानदार सिनेमाई अनुभव का वादा करती है। 'चतुर्ब' और 'सालार' जैसी बैक-टू-बैक ब्लॉकबस्टर फिल्में देने के बाद, फैंस यह देखने के लिए बेताब हैं कि प्रशांत नील अब क्या नया लेकर आएंगे। 'मैन ऑफ द मासेज' जूनियर एनटीआर के साथ उनका यह तालमेल भारतीय सिनेमा के सबसे ताकतवर मेल में से एक माना जा रहा है।फिल्म के ऐलान के बाद से ही इसे लेकर जबरदस्त हलचल है और फैंस हर छोटे अपडेट का इंतज़ार कर रहे हैं। दो इतने बड़े नामों के साथ आने से यह फिल्म साल की सबसे प्रतीक्षित फिल्मों में से एक बन गई है और हर कोई यह देखने को उत्सुक है कि यह मेगा कॉलैबोरेशन बड़े पर्दे पर क्या कमाल दिखाता है। प्रशांत नील के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में एनटीआर लीड रोल में हैं।

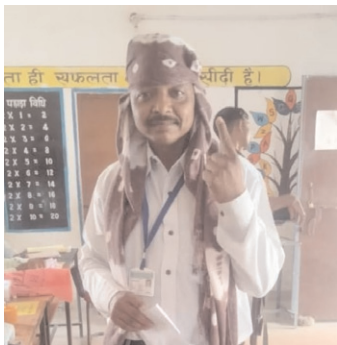
मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर शिक्षक ने दी जान, सुसाइड नोट में गंभीर आरोप; न्याय की मांग को लेकर चक्काजाम

बीजापुर/मूक पत्रिका

जिले में एक वरिष्ठ शिक्षक द्वारा आत्महत्या किए जाने की घटना के बाद पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है। पालनर क्षेत्र में पदस्थ प्रधान अध्यापक राजू पुजारी ने कथित तौर पर मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर यह कदम उठाया। जानकारी के अनुसार, वे सुबह करीब 8 बजे घर से निकले थे, लेकिन दोपहर तक वापस नहीं लौटे। चिंतित परिजन उनकी तलाश में निकले तो चेरपाल के बड़े तालाब के पास जंगल में उनका शव मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया।

सुसाइड नोट में लगाए गंभीर आरोप – जांच के दौरान पुलिस को मृतक के पास से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है। इसमें उन्होंने मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने का जिक्र करते हुए कुछ लोगों के नाम लिखे हैं। इस खुलासे के बाद मामला और गंभीर हो गया है। परिजनों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

परिजनों ने बताया पहले से चल रही



परेशानी –परिजनों के मुताबिक, करीब एक सप्ताह पहले मृतक को कार्यालय बुलाया गया था, जिसके बाद से वे लगातार तनाव में थे। उन्होंने घर में भी अपनी परेशानी जाहिर करते हुए कहा था कि उन्हें इस हद तक प्रताड़ित किया जा रहा है कि अब जीना मुश्किल हो गया है। इस बयान ने पूरे मामले को और संवेदनशील बना दिया है।

जिला अस्पताल के सामने चक्काजाम, बढ़ा तनाव –घटना के विरोध में परिजन और तेलंगा समाज के लोग जिला अस्पताल के सामने एकत्र हुए और चक्काजाम कर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने 'हमें न्याय चाहिए' और

'प्रताड़ना बंद करो' जैसे नारे लगाते हुए आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। इस दौरान कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा और माहौल तनावपूर्ण हो गया।

प्रशासन ने दिया कार्रवाई का भरोसा – कोतवाली थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा ने बताया कि पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। सुसाइड नोट को अहम साक्ष्य मानते हुए संबंधित लोगों से पूछताछ की जा रही है। उन्होंने कहा कि दोषी पाए जाने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं एसडीएम जगेश्वर कौशल ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों से चर्चा की और

निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया, जिसके बाद स्थिति कुछ हद तक सामान्य हुई।

जनप्रतिनिधियों ने उठाए सवाल, तीन दिन का अल्टीमेटम–विधायक विक्रम मंडावी ने मामले को गंभीर बताते हुए सुसाइड नोट में जिन तीन लोगों के नाम हैं, उनसे तत्काल पूछताछ और कार्रवाई की मांग की। उन्होंने शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की भी जांच करने की बात कही। विधायक ने प्रशासन को तीन दिन का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी कि तय समय में कार्रवाई नहीं होने पर चौथे दिन तेलंगा समाज और आम लोगों के साथ कोतवाली थाने

का घेराव किया जाएगा।

समाज ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी –सर्व आदिवासी समाज के सचिव कमलेश पैकरा ने घटना को बेहद दुःखद बताते हुए कहा कि समाज पीड़ित परिवार के साथ है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समय सीमा के भीतर कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन और जिला बंद का निर्णय लिया जाएगा। फ्लिहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और सुसाइड नोट के आधार पर आगे की कार्रवाई जारी है। यह घटना प्रशासनिक कार्यप्रणाली और कर्मचारियों पर बढ़ते दबाव को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रही है।



निधन समाचार

चांपा । स्थानीय रहस्यबद्ध समलेश्वरी मंदिर चौक निवासी गुप्ता समाज के प्रतिष्ठित नागरिक अनूप गुप्ता का बुधवार 22 अप्रैल को निवास पर सुबह 10 बजे निधन हो गया। वे 65 वर्ष के थे। स्व. अनूप गुप्ता अपने पीछे पूरा परिवार छोड़ गये है। वे दीपक गुप्ता,राजन गुप्ता,संदीप गुप्ता,पिटू गुप्ता के चाचा एवं आकाश गुप्ता व सागर गुप्ता के पिता थे। उनका अंतिम संस्कार बुधवार की शाम 5 बजे हस्देव नदी के तट पर भैंसा बाजार स्थित मुक्तिधाम में किया गया,जहाँ बड़ी संख्या में परिजन,सजातीय बंधुओं के अलावा गणमान्य नागरिक मौजूद थे ।

चमत्कार के नाम पर अनाचार: ढोंगी बाबा गिरफ्तार, महिला से दुष्कर्म और सोशल मीडिया ब्लैकमेलिंग का सनसनीखेज खुलासा, हिमाचल से दबोचा गया आरोपी 'निर्मल बाबा'

जांजगीर-चांपा/मूक पत्रिका

चमत्कार और इलाज के नाम पर महिलाओं को अपने जाल में फंसाने वाले एक ढोंगी बाबा का भंडाफेड़ करते हुए जांजगीर-चांपा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना पामगढ़ पुलिस ने महिला से अनाचार और सोशल मीडिया के जरिए ब्लैकमेल करने के गंभीर मामले में आरोपी स्वामी निर्मल उर्फ निर्मल बाबा (60 वर्ष) को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। आरोपी मूल रूप से नाशिक (महाराष्ट्र) का निवासी है और खुद को चमत्कारी बाबा बताकर लोगों की शारीरिक व मानसिक समस्याएं ठीक करने का दावा करता था।

इलाज के झूसे में फंसार किया अनाचार–पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पीड़िता ने 11 अप्रैल 2026 को थाना पामगढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया कि चैत्र नवरात्रि के दौरान आरोपी पामगढ़ क्षेत्र के एक गांव में पदयात्रा करते हुए आया था। इसी दौरान उसने खुद को चमत्कारी बाबा बताते हुए इलाज का भरोसा दिलाया और पीड़िता का मोबाइल नंबर हासिल कर लिया। 26 मार्च को आरोपी ने पीड़िता को पामगढ़



फेन कॉल्स से परेशान होकर उसका नंबर ब्लॉक किया, तो आरोपी ने बदले की नीयत से पीड़िता के नाम से फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर अश्लील फोटो पोस्ट कर दी और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर ब्लैकमेल करने लगा।

महिला के साथ घटित गंभीर अपराध को देखते हुए निवेदिता पाल ,प्रभारी पुलिस अधीक्षक के निर्देशन और उमेश कुमार कश्यप ,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में विशेष टीम गठित की गई। SDOP प्रदीप कुमार सोरी के नेतृत्व में थाना पामगढ़ पुलिस ने 21 अप्रैल 2026 को धर्मशाला में दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया।पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया, जिसके बाद उसके विरुद्ध ब्रह्म की धारा 64(2)(ए) एवं आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। इस पूरी कार्रवाई में निरीक्षण सावन सारथी (थाना प्रभारी पामगढ़), प्रधान आरक्षक रामलाल माकंडेय, आरक्षक सूरज सिंह पाटले एवं नवनी रात्रे का सराहनीय योगदान रहा।

बेमेतरा/मूक पत्रिका

जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष एवं बेमेतरा के पूर्व विधायक आशीष छबड़ा ने जिले में उर्वरक एवं उन्नत बीजों की कमी को लेकर छोटे दुकानदारों के ऊपर की जा रही कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि किसानों को पर्याप्त खाद बीज की आपूर्ति सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेवारी है भाजपा सरकार अपनी जिम्मेवारी एवं नाकामी से बचने के लिए छोटे एवं मझोले कृषि व्यापारियों को परेशान करने का काम कर रही है अगर सरकार चाहती है कि किसानों को सही समय पर खाद एवं बीज की आपूर्ति हो तो इसके लिए आवश्यक है कि सरकार पहले सेवा सहकारी समिति के माध्यम से पूरा खाद बीज वितरण कराए।उसके बाद निजी विक्रेताओं को दो।उर्वरक की हैडलिंग पूरा सरकार के हाथ में है।मुद्दों को भटका कर सरकार जिम्मेदारी से बच नहीं सकती.छोटे छोटे व्यापारियों पर कार्यवाही के लिए धमकाना और दिखावे की कार्यवाही औचित्य हीन है।इससे प्रशासन अपने कर्तव्यों से ध्यान भटकाने का उपाय के रूप में देखा जाएगा।अपनी जिम्मेदारी से सरकार बच नहीं सकती। किसानो को सही दाम पर रासायनिक उर्वरक और खाद बीज की सुनिश्चित



आपूर्ति बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है।,सरकार अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकती।जिले में वर्तमान में खरीफसीजन की मांग के मुकाबले भंडारण बहुत कम है।ऐसे में अपनी कमियां छुपाने सरकार और प्रशासन छोटे छोटे व्यापारियों को धमका कर अपने कर्तव्यों से छुटकारा पाने का प्रयास कर रही है।आज की स्थिति में बड़े मगरमच्छ सरकार को चढ़ावा दे कर खाद के काले कारनामों को अंजाम दे रहे है, ।कपनियां उर्वरक के साथ मनमानी रूप से लादन दे रही है, और उसे लदान को रासायनिक खाद्य के साथ खरीदने की जिम्मेवारी किसान को उठानी पड़ रही है जो पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ है उसे अतिरिक्त भार वहन करना पड़ रहा है उस पर कार्यवाही करने की बजाय प्रशासन बहुत छोटे व्यापारियों को डर भय दिखा कर सरकार की वाह वाही लूटने का प्रयास कर रहा है।जो सरासर गलत ,और निंदनीय है।सरकार को किसानो के हित के साथ इस तरह खिलवाड़ करने की कांग्रेस पार्टी

विरोध करेगी।कांग्रेस पार्टी भाजपा सरकार की गलत मंशा को उजागर करके जनता और किसानो के समक्ष लाएगी,और किसानो को उनका हक दिला कर रहेगी। यदि भाजपा सरकार की मंशा , किसानों को सही समय पर रासायनिक खाद एवं बी दिलावे की है तो तो उर्वरक निर्माता कंपनियों से टैरिंग रोकने प्रतिबंध लगाए।और सेवा सहकारी समितियों में पहले भरपूर खाद का मांग के अनुरूप प्रयाप्त भंडारण करारक किसानो को वितरण सुनिश्चित करे।वैसे भी भाजपा सरकार की मंशा किसान विरोधी है,इस खरीफसीजन में सबने देखा है कि खाद वितरण से लेकर धान खरीदी तक कैसे किसानो को इस सरकार की नीतियों से भारी परेशान होना पड़ है।3100 रुपया क्तिटल में पिछले तीन सालों से एक ही कीमत पर धान की खरीदी की जा रही है वह भी किस्तों में धान खरीदी सरकार का जुमला साबित हो चुका है। एग्री स्ट्रेक की सिरदई आज भी किसानो का पीछ नहीं छोड़ी है।ऐसे में सरकार मूल मुद्दे से ध्यान भटका कर,किसानो की उपज को कम करना चाह रही है,ताकि उसे किसानो की धान खरीदी से छुटकारा मिल जाए।लेकिन किसानो के हित के इस मुद्दे के लिए कांग्रेस पार्टी सड़क से ससंद तक संघर्ष करेगी ,और किसानो को समुचित और पर्याप्त खाद बीज आपूर्ति के लिए सरकार को बाध्य करेगी।।

क्रेशर से निकल रहे सैकड़ों वाहन, रॉयल्टी बचाने का खेल, खनिज जांच चौकियों की भूमिका पर उठे सवाल

टिמרलगा-गुड़ेली में अवैध खनन का जाल, बिना रॉयल्टी गिट्टी परिवहन जारी

रायगढ़/मूक पत्रिका

टिמרलगा और गुड़ेली क्षेत्र में अवैध खनन तथा बिना रॉयल्टी गिट्टी परिवहन का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। चंदपुर, टिמרलगा और गुड़ेली स्थित खदानों से रोजाना बड़ी संख्या में गिट्टी और लाइमस्टोन से लदे वाहन बिना ट्रांजिट पास (टीपी) के निकल रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि खनिज जांच चौकियों की मौजूदगी के बावजूद यह कारोबार खुलेआम जारी है, जिससे विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। जानकारी के मुताबिक टिמרलगा खनिज बैरियर में कर्मचारियों की तैनाती होने के बाद भी अवैध परिवहन में तेजी देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि रोज करीब सैकड़ों की संख्या में वाहन बिना वैध टीपी और कई बार ओवरलोड होकर रायगढ़, सक्की और ओडिशा की ओर रवाना हो रहे हैं। इससे सरकार को भारी राजस्व हानि होने की आशंका जताई जा रही है।इधर गुड़ेली और आसपास के क्षेत्रों में संचालित

कई क्रशर प्लांटों पर भी अवैध बोल्डर खपाए जाने के आरोप लग रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि कुछ क्रशर संचालक एक ही टीपी का बार-बार उपयोग कर कई ट्रिप भेज रहे हैं। इससे खनिज विभाग की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।हालांकि खनिज विभाग द्वारा समय समय

और बिना रॉयल्टी के अवैध गिट्टी परिवहन करने वाले वाहनों पर कार्यवाही तो की जाती है।परन्तु टिמרलगा खनिज जांच चौकी में यदि ईमानदारी से वाहनों के दस्तावेजों एवं रॉयल्टी की जांच होती तो संभवतः विभाग को कार्यवाही की आवश्यकता ही नहीं पड़ती।परन्तु रॉयल्टी बचाने के फेर में

थोड़ी सांठगांठ कर खनिज चौकी में तैनात कर्मियों द्वारा शासन को करोड़ों रुपए के राजस्व का चुना लगाया जा रहा है।

रॉयल्टी बचाने का खेल-सूत्रों के मुताबिक अवैध परिवहन के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं। सबसे आम तरीका बिना टीपी के सीधे वाहन

भेजना है। क्रशर से गिट्टी लोड कर वाहन रायगढ़, सक्की और ओडिशा की ओर रवाना कर दिए जाते हैं। रास्ते में जांच होने की स्थिति में फर्जी पर्ची या पुराने टीपी दिखाकर वाहन को निकालने की कोशिश की जाती है। दूसरा तरीका एक ही टीपी का बार-बार उपयोग करना है। नियम के अनुसार

एक टीपी केवल एक ट्रिप के लिए मान्य होता है, लेकिन कुछ संचालक उसी टीपी को कई बार इस्तेमाल कर कई ट्रिप में गिट्टी भेज देते हैं। इससे एक ही रॉयल्टी में कई गाड़ियों का परिवहन हो जाता है।तीसरा तरीका फर्जी रॉयल्टी जारी कराने का बताया जा रहा है। आरोप है कि कुछ लीजधारक नाम मात्र का खनन दिखाकर बड़ी मात्रा में रॉयल्टी पर्चियां प्राप्त कर लेते हैं और बाद में उन्हें अन्य क्रशर संचालकों को बेच देते हैं। इस तरह बिना वास्तविक खनन के भी गिट्टी का परिवहन जारी रहता है।

जांच चौकी की खानापूर्ति

टिमीरलगा गुड़ेली मार्ग में स्थित खनिज जांच चौकी में जांच के नाम पर महज रस्म अदायगी देखने को मिलती है।जहां से सेटिंग किए गए वाहनों को बिना जांच के ही कुछ पैसे लेकर छोड़ दिया जाता है।बताया जा रहा है कि इस चौकी की खनिज विभाग में पदस्थ कर्मचारी तो गैर मौजूद रहते हैं।अलबता इसकी जिम्मेदारी बाहरी रखे गए लोगों के हाथों में होती है।

संपादकीय

तमिलनाडु में इस मसले पर व्यापक असंतोष उभर रहा है। तेलंगाना, कर्नाटक और केरल आदि राज्यों में भी परिसीमन में आबादी के आधार पर लोकसभा की सीटों में वृद्धि होने पर तीखे सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या दक्षिण भारतीय राज्यों को परिवार नियोजन को लेकर बेहतर प्रदर्शन का खमियाजा उठाना पड़ रहा है। एक संवेदनशील मुद्दे पर देश के अलग-अलग राज्यों में इस स्तर के मतभेद पैदा नहीं होने चाहिए थे और इससे जुड़ी चिंताओं का समाधान वक्त की जरूरत है। इसमें कोई दोराय नहीं कि संसद में सीटों की संख्या में बढ़ोतरी समय की जरूरत हो सकती है और निर्धारित प्रक्रिया के तहत इसमें बदलाव हो सकते हैं। मगर इस वर्ष परिसीमन की कवायद को लेकर कई सवाल उभरते दिख रहे हैं। खासतौर पर दक्षिण भारत के राज्यों की ओर से यह

आशंका जताई जा रही है कि परिसीमन के ताजा प्रस्ताव के तहत जो प्रारूप सामने आया है, अगर वह अमल में आया तो यह व्यापक स्तर पर भेदभाव का कारण बनेगा। हालांकि इस तरह के कदम उठाने से पहले देशभर में सर्वसम्मति कायम करने की अपेक्षा की जाती है, ताकि राज्यों के बीच मतभेद न उपजे, लेकिन परिसीमन को लेकर केंद्र सरकार की पहल के बाद तमिलनाडु में जिस तरह का विरोध उभर रहा है, उससे कई सवाल उठे हैं। गौरतलब है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने गुरुवार को केंद्र के प्रस्तावित परिसीमन की कवायद के खिलाफ विरोध को तेज करते हुए इससे संबंधित विधेयक की प्रति जला कर और काला झंडा दिखा कर पूरे राज्य में आंदोलन की शुरुआत कर दी। इससे पहले स्टालिन ने यहां तक कहा था कि

तमिलनाडु की चिंता को दूर किए बिना अगर परिसीमन को आगे बढ़ाया गया, तो राज्य में एक समय चले हिंदी विरोधी आंदोलनों जैसी स्थिति बन सकती है।निश्चित रूप से एक संवेदनशील मुद्दे पर देश के अलग-अलग राज्यों में इस स्तर के मतभेद पैदा नहीं होने चाहिए थे और इससे जुड़ी चिंताओं का समाधान वक्त की जरूरत है। मगर हैरानी की बात यह है कि क्या केंद्र सरकार को इसका आभास नहीं था कि लोकसभा में सीटों की संख्या में बढ़ोतरी के क्रम में उत्तर और दक्षिण भारत के राज्यों के बीच जिस तरह का असंतुलन पैदा होने वाला है, उससे कई स्तर पर असंतोष उभर सकता है! दरअसल, सरकार परिसीमन को महिला आरक्षण के साथ जोड़ कर पेश करने का प्रयास कर रही है, ताकि इसे लेकर उठने वाली आपत्तियों को कमजोर किया जा सके।मगर

विपक्षी दलों की ओर से ऐसे सवाल उठाए जा रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर अलग-अलग राज्यों में लोकसभा की सीटों में बढ़ोतरी संसद के समीकरण में वैसे राज्यों को मजबूत स्थिति में खड़ा करेगा, जहां भारतीय जनता पार्टी ताकतवर है। सीटों के फिर से बंटवारे के क्रम में जो नया समीकरण बनेगा, उसमें दक्षिण भारत के राज्यों के प्रतिनिधित्व और अधिकारों में काफी कमी आने की आशंका जताई जा रही है। दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे कई राज्यों की नुमाइंदगी में काफी बढ़ोतरी हो जाएगी।शायद यही वजह है कि तमिलनाडु में इस मसले पर व्यापक असंतोष उभर रहा है। तेलंगाना, कर्नाटक और केरल आदि राज्यों में भी परिसीमन में आबादी के आधार पर लोकसभा की सीटों में वृद्धि होने पर तीखे सवाल उठाए जा रहे हैं।

आधी आबादी बनाम आधी सोच- सदन में ठहरा न्याय

आधी आबादी बनाम आधी सोच- सदन में ठहरा न्यायलोकतंत्र केवल बहुमत का खेल नहीं, वह मूल्य और मर्यादा का विधान भी है। और जब वही लोकतंत्र उस प्रस्ताव के सामने ठहर जाए, जो आधी आबादी को निर्णय के केंद्र में स्थापित करने का साहस रखता हो, तब प्रश्न केवल एक विधेयक का नहीं, उस सोच का होता है, जो परिवर्तन से कतराती है। ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ के लिए आवश्यक संविधान संशोधन बिल का सदन में पारित न हो पाना एक राजनीतिक घटना भर नहीं है, यह उस मानसिकता का अनावरण है, जो नारी के सम्मान की बातें तो करती है, पर उसे सत्ता-संरचना में वास्तविक स्थान देने से हिचकती है।

(प्रणय विक्रम सिंह)

भारतीय संस्कृति में नारी केवल शक्ति नहीं, बल्कि ‘मेधा’ और ‘लोक-मंगल’ की अधिष्ठात्री रही है। यह वही भूमि है जहां गांगी प्रश्न करती हैं, मैत्रेयी ज्ञान को सर्वोपरि मानती हैं और द्रौपदी सत्ता से धर्म का उत्तर मांगती है। ऐसे देश में नारी के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सीमित रखना केवल विरोधाभास नहीं, बल्कि सांस्कृतिक विस्मरण है। ‘नारी वंदन अधिनियम’ उसी सनातन संस्कार का आधुनिक संसदीय रूप था, जहां परंपरा नीति में रूपांतरित होती और श्रद्धा व्यवस्था में प्रतिष्ठित होती।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह केवल एक राजनीतिक पहल नहीं थी, बल्कि एक व्यापक दृष्टि का विस्तार थी, ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ का स्वाभाविक उत्कर्ष, जिसमें नारी केवल सहभागी नहीं, बल्कि सह-निर्माता बनती है। जनधन, उज्ज्वला, शौचालय, मातृत्व सुरक्षा और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से जो आधार निर्मित हुआ, वही इस अधिनियम में अपनी तार्किक परिणति पाता।

परंतु संसद में जो हुआ, वह केवल एक विधेयक का रकना नहीं है, यह भारत की वैचारिक परंपरा के साथ एक विचलन का क्षण है।

ज्ञातव्य है कि महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत, अर्थात 352 मतों की आवश्यकता थी। किंतु इसके पक्ष में मात्र 298 मत ही प्राप्त हो सके, जबकि 230 सांसदों ने इसका विरोध किया और इसी के साथ यह ऐतिहासिक अवसर अधूरा रह गया।

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के तर्क न केवल विरोधाभासी थे, बल्कि वे इस मूल प्रश्न से भी विमुख दिखाई दिए कि क्या नारी को समान प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए या नहीं। वैसे भी मातृशक्ति को अधिकार देने के मामलों में कांग्रेस हमेशा पीछे हटी है। शाहबानो मामले में पीछे हटी, ट्रिपल तलाक में पीछे हटी और अब महिला आरक्षण में भी पीछे हट गई।

वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने तुष्टीकरण की एक नई रेखा खींचते हुए महिला आरक्षण के भीतर अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए पृथक कोटा की मांग कर दी। यह मांग न केवल व्यावहारिक दृष्टि से असंगत है, बल्कि सिद्धांततः भी संविधान की मूल भावना के प्रतिकूल है। भारतीय संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था को स्वीकार नहीं करता है।

संसद में केवल एक प्रस्ताव नहीं ठहराज ठहर गया डॉ. भीमराव आंबेडकर का वह संवैधानिक स्वप्न, जिसमें समानता केवल शब्द नहीं, अधिकार थी।

डॉ. राम मनोहर लोहिया का वह सामाजिक संघर्ष ठहर गया, जो स्त्री-पुरुष समानता को लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त मानता था।जयप्रकाश नारायण का वह लोकनैतिक आग्रह ठहर गया, जिसमें सत्ता को समाज के प्रति उत्तरदायी होना था।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की वह कल्पना भी ठहर गई, जिसमें नारी को नैतिक नेतृत्व का केंद्र माना गया था। और यह केवल उत्तर भारत की चेतना नहीं थी, दक्षिण की धरती पर सावित्रीबाई फुले के संघर्ष से लेकर परियार के

सामाजिक विद्रोह तक, नारायण गुरु के समता संदेश से लेकर किट्टर रानी चैनम्मा के साहस तक, हर धारा ने नारी को केवल सहायक नहीं, बल्कि परिवर्तन का अग्रदूत माना। वे सब हार गए क्योंकि उनका मूल विश्वास यहीं था कि लोकतंत्र तब तक अधूरा है, जब तक उसमें नारी की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित न हो।

दुर्भाग्य यह रहा कि विपक्ष ने इस ऐतिहासिक अवसर को अपनी संकीर्ण राजनीति की भेंट चढ़ा दिया। जिस विषय पर राष्ट्र एकमत हो सकता था, वहां विरोध केवल असहमति नहीं, बल्कि उस परिवर्तन के प्रति भय का संकेत है, जो स्थापित समीकरणों को तोड़ देता है। यह विरोध तर्क का नहीं, सत्ता के संरक्षण का था।

यह दृश्य अनायास ही महाभारत की उस सभा की स्मृति जगा देता है जहां द्रौपदी प्रश्न कर रही थी और सत्ता मौन



थी। उस दिन केवल दुशासन दोषी नहीं था, वह मौन भी दोषी था, जिसने अन्याय को होने दिया। आज भी प्रश्न वही हैज क्या हम फिर उसी मौन के सहभागी बन रहे हैं?

यह केवल विधेयक का गिरना नहीं था, यह उस अवसर का चूकना था, जहां भारतीय लोकतंत्र स्वयं को और अधिक समावेशी और संतुलित बना सकता था। यह उस विश्वास पर आघात था, जो करोड़ों महिलाओं ने इस आशा के साथ जोड़ा था कि अब उनकी आवाज निर्णयों में दिखाई देगी।

परंतु इतिहास साक्षी है कि भारत में नारी कभी पराजित नहीं होती। प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने इस विषय को जिस स्पष्टता और दृढ़ता से उठाया है, वह यह सिद्ध करता है कि यह संघर्ष रुकने वाला नहीं है। क्योंकि यह किसी दल का नहीं, भारत की आत्मा का प्रश्न है।

अब प्रश्न है कि इस संशोधन अधिनियम की सियासी बिसात पर कौन जीता? विपक्ष भले ही अपनी जीत का जश्न मना रहा हो किंतु इस बिसात पर चित और पट दोनों ही पक्ष भाजपा के साथ दिखाई देते हैं।

ध्यातव्य है कि यदि विधेयक लोकसभा में पारित हो जाता, तो यह नारी सशक्तीकरण की ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में भाजपा के खाते में जाता और अब जब यह ठहर गया है, तब विपक्ष का नारी विरोधी चरित्र उजागर हो गया है।

पार्टी ने इस मुद्दे को तुरंत जनआंदोलन का रूप देते हुए अपनी महिला सांसदों को आगे किया है, धरना-प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं और विपक्ष पर सीधे हमले तेज हो गए हैं। यह मुद्दा भावनात्मक हो गया है। आधी आबादी की संसद से सड़क तक पीड़ा दिखने लगी है। स्थिति यह है कि विपक्ष, विधेयक को रोककर भी सहज नहीं है। उसके नेता भले ही अपनी ‘रणनीतिक जीत’ पर संतोष व्यक्त कर रहे हों, लेकिन जनमानस में उठ रहे प्रश्न और भाजपा की आक्रामक रणनीति ने उन्हें रक्षात्मक स्थिति में ला खड़ा



किया है।

आश्चर्य होता है कि लोकसभा चुनाव के समय जो दल ‘संविधान बचाने’ की दुहाई दे रहे थे, उन्होंने ही डॉ. आंबेडकर के संवैधानिक स्वप्न (समानता) का पला घोंटा है। विपक्ष का असाधारण दोहरापन एक बार फिर बेनकाब हो गया।

बिदित हो कि जब-जब इतिहास ने कठिन प्रश्न खड़े किए हैं, तब-तब इसी परंपरा ने उत्तर दिया है। धारा 370 का अंत हो, 35ए का निष्कासन, अयोध्या में श्रीराम मंदिर का स्वप्न साकार होना या सीएए जैसा साहसिक निर्णय हर बार असंभव को संभव करने का संकल्प इसी विचारधारा ने निभाया है।

अब पुनः वही क्षण है।

आधी आबादी को नेतृत्व में भागीदारी अब केवल एक विधेयक का प्रश्न नहीं रहा, यह राष्ट्रव्यापी जनचेतना का विषय बन चुका है।

सदन भले ठहर गया हो पर समाज चल पड़ा है। ऊपर व्यक्त विचार लेखक के अपने हैं।

कमजोर मानसून और आपदा प्रबंधन

(डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा)

हमारे देश में मानसूनी बरसात पर निर्भरता अधिक है। जहां खेती में मानसूनी बरसात की निर्भरता बहुत अधिक है तो दूसरी ओर पेयजल को लेकर भी मानसून पर निर्भरता अधिक है। जलाशयों में पानी के भण्डारण और भूजल स्तर भी बरसाती पानी पर ही निर्भर है। हमारी खेती मुख्यतः मानसून पर निर्भर हैं। आगामी मानसून को लेकर के पहला पूर्वानुमान जारी करने के साथ ही मौसम विभाग ने आने वाले मानसूनी सत्र में सामान्य से कम बरसात के संकेत दे दिए हैं। हालांकि अभी मानसून के पूर्वानुमान और भी जारी किये जाएंगे पर यह आरंभिक सूचना आने वाले समय के लिए गंभीर संकेत है।

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार सामान्य से 8 फीसदी तक कम बरसात की संभावना जताई गई है। देश के कई हिस्सों में कम बरसात होने के संकेत है तो कुछ हिस्सों में सामान्य बरसात भी हो सकती है। माना जा रहा है कि अल नीनो इफेक्ट के चलते मानसून कमजोर रहेगा। यह भी सही है कि हमारे मौसम मंत्रालय द्वारा जारी पूर्वानुमान अब काफी हद तक आसपास रहने लगे हैं। यहां तक कि दो से तीन घंटों में बरसात होने या आंधी तूफान या ओलावृष्टि तक के पूर्वानुमान खरे उतरने लगे हैं। ऐसे में मौसम विभाग के पूर्वानुमानों को गंभीरता से लेते हुए केन्द्र व राज्यों की सरकारों को अभी से पूर्व तैयारियां करने में जुट जाना चाहिए। खासतौर से आपदा प्रबंधन मंत्रालय को अभी से भावी रणनीति तय करनी होगी। देश में मानसून सीजन में 87 सेमी बरसात होती है जिसके अनुमानों के अनुसार 81 सेमी तक रहने की आशंका है। पूर्वानुमानों को माने तो 2018 में 91 प्रतिशत बरसात हुई थी उसके बाद के सालों में मानसून लगभग अच्छा ही रहा है। पिछले आठ सालों में मानसून की स्थिति देखें तो 2023 में मानसून अवश्य कमजोर रहा है अन्यथा देश में मानसूनी वर्षा 100 प्रतिशत के आसापास व इससे अधिक हो रही है।

हमारे देश में मानसूनी बरसात पर निर्भरता अधिक है। जहां खेती में मानसूनी बरसात की निर्भरता बहुत अधिक है तो दूसरी ओर पेयजल को लेकर भी मानसून पर निर्भरता अधिक है। जलाशयों में पानी के भण्डारण और भूजल स्तर भी बरसाती पानी पर ही निर्भर है। हमारी खेती मुख्यतः मानसून पर निर्भर हैं। सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता कमी के कारण मानसून पर खेती 55 से 64 प्रतिशत निर्भर है। पीने के पानी की समस्या भी कमजोर मानसून से प्रभावित होती है। हमारे यहां मानसून का समय जून से सितंबर तक का रहता

है। अब सवाल उठता है कि पिछले सालों में मानसून सामान्य से अच्छा रहने के बावजूद कमजोर मानसून की



स्थिति से निपटने में हमारी तैयारी कोई अच्छी नहीं मानी जा सकती। अत्यधिक भूजल दोहन और जल संचयन की दीर्घकालीक नीति के अभाव में ठोस परिणाम प्राप्त नहीं हो पाये हैं। ऐसा नहीं है कि नीति नहीं बनती हो या ऐसा भी नहीं है कि जल संचयन के प्रयास नहीं होते हो पर जो परिणाम देखने में आए हैं वह कोई आशाजनक नहीं माने जा सकते। पानी के विवेकपूर्ण उपयोग की बात करना तो हमारे यहां बेमानी हो रही है। प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण व संधारण में भी हम कुछ अधिक नहीं कर पाये हैं। इसके अलावा हमारे यहां दुर्भाग्यजनक बात यह है कि तात्कालिक प्रयास होते हैं। शहरीकरण की आड़ में प्राकृतिक जल स्रोत या तो नष्ट हो गए हैं या उनमें बरसात के पानी जाने के रास्ते अवरुद्ध या बंद हो गए हैं। नदी नालों के रास्ते या तो बंद हो गए हैं या अवरुद्ध हो गए हैं। बरसात के पानी के जलाशयों में

रास्तों में अनधिकृत कब्जें, निर्माण और रिसोर्ट बना दिए हैं। एक समय ऐसा भी आया कि जब विशेषज्ञों ने

बरसात के पानी जाने के रास्तों में जगह जगह एनिकट बनाने की सलाह दे डाली और छोटे छोटे एनिकट बनने से नदियों-जलाशयों में पानी की आवक प्रभावित हो गई। इससे तात्कालीक यानी कि एनिकटों में पहले पानी एकत्र तो हुआ पर बाद में इनका रख रखाव नहीं होने से दोहरा नुकसान हुआ। इसी

तरह से वर्षा जल संचयन के लिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए सरकार ने अरबों रुपये खर्च किये पर उनके निर्माण के आंकड़ें पूरे करने के चक्कर में हम भूल गए कि बरसात के पानी इनमें कितना व कैसे जा पाएगा। फिर बरसात से पहले इनकी देखरेख पर भी ध्यान नहीं देने से जो परिणाम मिलने चाहिए थे वे नहीं मिल सके हैं। एक और हमारे दैनिक उपभोग में भी पानी का उपयोग अधिक बढ़ा है आज पेयजल से कई गुणा अधिक पानी टायलेट और कुलों में उपयोग होने लगा है। समय रहते टायलेट में कम पानी के उपयोग की कोई रह निकाली जाती तो हालात में सुधार ही होता। इसी तरह से देशभर में वाटर ट्रिंमेंट सिस्टम लगाने का अभियान चला पर इनके परिणाम भी ज्यादा अच्छे नहीं देखे जा रहे है। रिसाइकिल पानी को लेकर भी कोई स्पष्ट नीति तय हो तो कुछ हद तक समाधान हो सकता है। खैर यह तो

हालात की तस्वीर है।

सी टूके का सवाल यह है कि कमजोर मानसून के हालात से निपटने की कार्ययोजना हमें अभी से बनानी होगी। मौसम विभाग ने अप्रैल में यह चेतावनी दे दी है। मानसून जून में आएगा। ऐसे में अभी मई का महीना हमारे पास है। अभी से सरकार को कमर कसनी होगी। कमजोर मानसून के हालात में हमें कम पानी से अधिक बेहतर हालात बनाने के प्रयास करने होंगे। इसके लिए जहां पानी की एक एक बूंद को सहेजने की रणनीति तैयार करनी होगी वहीं कृषि मंत्रालय को खरीफ के लिए इस तरह की रणनीति बनानी होगी जिसमें कम पानी के उपयोग से बेहतर फसल तैयार होने वाली फसलों और किस्मों के लिए किसानों को प्रेरित हो सकें। खेती किसानी भी प्रभावित ना हो और पैदावार भी अच्छी हो इसकी रणनीति बनानी होगी। अधिक पानी की आवश्यकता वाली फसलों की खेती ना करने के लिए किसानों को उत्साहित करना होगा। इसी तरह से जलाशयों, बांधों में उपलब्ध पानी का प्रबंधन योजनाबद्ध तरीके से करना होगा। अभी से आमजन को पानी के अपव्यय को रोकने के लिए प्रेरित करना होगा। कहने का अर्थ है कि जब आने वाले हालात की तस्वीर हमारे सामने कमोबेस आ चुकी है तो फिर समय रहते इस तरह की रणनीति बनानी होगी ताकि कमजोर मानसून में भी हमारी जल प्रबंधन क्षमता बेहतर रह सके। आपदा प्रबंधन मंत्रालय को अभी से संबंधित मंत्रालयों खासतौर से कृषि, जल आपूर्ति करने वाले विभागों, बांधों एवं जलाशयों का प्रबंधन करने वाले विभागों, जल संसाधन विभागों से समन्वय बनाकर रणनीति तैयार करनी होगी। इसके साथ ही आमजन को भी पानी के उपयोग को लेकर अधिक सजग और जिम्मेदार नागरिक के रुप में भूमिका निभानी होगी। (ब्रह्म लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

निवा बूपा ने पेश की यंग इंडिया हेल्थ इंश्योरेंस रिपोर्ततैयारी मापने के लिए पहली बार लॉन्च किया हेल्थ प्रोटेक्शन स्कोर

गुरुग्राम: निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस ने आज अपने सालाना मुख्य इवेंट बेटर टुगेदर में यंग इंडिया हेल्थ इंश्योरेंस रिपोर्ट झू इंडियाज़ हेल्थ प्रोटेक्शन स्कोर को पेश किया। यह इवेंट कंपनी के पार्टनर्स और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से जुड़े लीडर्स का एक बड़ा जमावड़ा है। यह कार्यक्रम आपसी बातचीत को बढ़ावा देने, तालमेल को मजबूत करने और हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर के भविष्य की योजना बनाने के लिए एक रणनीतिक मंच के रूप में काम करता है—जिसमें ग्राहकों की जरूरतों को सबसे ऊपर रखा जाता है।

यंग इंडिया रिपोर्ट एक सर्वेक्षण पर आधारित है जो 35+ शहरी और ग्रामीण केंद्रों के 2,400+ उपरदाताओं के बीच किया गया था, जिसमें टियर 1, 2 और 3 शहरों के साथ-साथ गाँव भी शामिल हैं। यह युवा उपभोक्ताओं के बीच स्वास्थ्य बीमा के प्रति जागरूकता और वास्तविक स्वात्मित्व के बीच एक बड़े अंतर को उजागर करता है। जबकि 51 प्रतिशत युवा भारतीय स्वास्थ्य बीमा को अपनी शीर्ष तीन वित्तीय प्राथमिकताओं में रखते हैं—जो एक मजबूत इरादे को दर्शाता है—केवल 14 प्रतिशत के पास वर्तमान में व्यक्तिगत पॉलिसी है, जो जागरूकता और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट अंतर को प्रकट करता है। रिपोर्ट की एक मुख्य विशेषता हेल्थ प्रोटेक्शन स्कोर (HPS) की शुरुआत है—यह अपनी तरह का पहला कंपोजिट मेट्रिक (मिश्रित पैमाना) है जिसे यह आंकने के लिए बनाया गया है कि युवा भारतीय मेडिकल इमरजेंसी से निपटने के लिए कितने तैयार हैं। यह स्कोर चार महत्वपूर्ण पहलुओं को एक साथ लाता है: 1) जीवनशैली का अनुशासन, 2) परिवार का स्वास्थ्य इतिहास, 3) स्वास्थ्य स्थिति और देखभाल का स्व- मूल्यांकन, और 4) वित्तीय पर्याप्तता—जो केवल बीमा होने से कहीं आगे बढ़कर स्वास्थ्य संबंधी तैयारी का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है।

हेल्थ प्रोटेक्शन स्कोर ने एक असुरक्षित युवा भारत का खुलासा किया- हेल्थ प्रोटेक्शन स्कोर के निष्कर्ष भारत की स्वास्थ्य तैयारी के परिदृश्य की एक आकर्षक और कुछ हद तक विरोधाभासी तस्वीर पेश करते हैं। समग्र स्वास्थ्य की एक अपुष्ट (बिना जाँची हुई) भावना के भरोसे, युवा भारत ने हेल्थ प्रोटेक्शन स्कोर पर 4.54 का कम स्कोर हासिल किया है, जो मेडिकल इमरजेंसी को संभालने के लिए अपर्याप्त तैयारी का संकेत देता है।

मोटोरोला ने लॉन्च किया मोटोरोला एज 70 प्रो

बिलासपुर। मोबाइल टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में वैश्विक अग्रणी और भारत के प्रमुख एआई स्मार्टफोन ब्रांड, मोटोरोला ने आज मोटोरोला एज 70 प्रो लॉन्च किया, जिसे उन्नत लो-लाइट फोटोग्राफी, शानदार विजुअल्स और अगली पीढ़ी के ऑन-डिवाइस एआई के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को सीज़ द नाइट में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस डिवाइस में motoAI के साथ एडवांस्ड सोनी-LYTIA™ 710 कैमरा द्वारा संचालित ट्रिपल 50MP प्रो-ग्रेड कैमरा सिस्टम है, जो शानदार नाइट फोटोग्राफी, लो-लाइट क्लैरिटी, ब्लर-फ्री शॉट्स, पैंटोनर बैलिडेटेड टू कलर्स और स्किकनोन™ सटीकता के साथ सभी कैमरों पर 4K 60FPS वीडियो प्रदान करता है। मीडियाटेक डाइमेंसिटी 8500 एक्सट्रीम द्वारा संचालित, यह उन्नत ऑन-डिवाइस एआई प्रोसेसिंग के साथ लो- लाइट इमेजिंग को और बेहतर बनाता है। मोटोरोला एज 70 प्रो में मोटोरोला द्वारा बिल्कुल नया कलेक्शंस डिज़ाइन भी पेश किया गया है, जिसमें पैंटोन™ क्यूरेटेड रंगों में शानदार सैटिन-लक्स, टेलर्ड फैब्रिक और मार्बल फ़िनिश शामिल हैं, जिसे 144H5 तक के 1.5K टू कलर™ ब्रांड-कर्व्ड पैंटोन™ बैलिडेटेड एक्सट्रीम एमोलेड डिस्प्ले के साथ जोड़ा गया है। 90W टर्बोचार्ज चार्जिंग और IP68 + IP69 ड्यूरेबिलिटी के साथ विशाल 6500mAh सिलिकॉन-कार्बन बैटरी द्वारा समर्थित, यह डिवाइस एक वास्तविक फ्लैगशिप-ग्रेड स्मार्टफोन अनुभव प्रदान करता है। मोटोरोला एज 70 प्रो अपने उन्नत 50MP सोनी LYTIA™ 710 कैमरा और motoAI की शक्ति के साथ इमेजिंग के क्षेत्र में एक नया बेंचमार्क स्थापित करता है, जो असाधारण स्पष्टता, बेहतर सिग्नल-टू-नॉइज़ परफॉर्मेंस और ब्राइट हाइलाइट्स व डीपर शैडो के साथ शानदार लो-लाइट परिणाम देता है।

लुइसियाना में घरेलू कलह के चलते हुई गोलीबारी, आठ बच्चों की दर्दनाक मौत

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका के लुइसियाना में गोलीबारी की दर्दनाक घटना हुई है। इस घटना में एक से 14 साल के आठ बच्चों की मौत हो गई है। पुलिस ने इसकी पुष्टि की है। पुलिस ने बताया कि घरेलू कलह के चलते ये घटना हुई। फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुटी है। घटना रविवार तड़के श्रेवपोर्ट इलाके में हुई। श्रेवपोर्ट पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि घटना में कुल 10 लोगों को गोली लगी, जिनमें कुछ बच्चे संदिग्ध हमलावर के रिश्तेदार भी थे । गोलीबारी में आठ बच्चों की मौत की पुष्टि हुई है। मृतकों की उम्र एक वर्ष से लेकर लगभग 14 वर्ष तक बताई गई है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी की बाद में पुलिस के साथ मुठभेड़ के दौरान मौत हो गई। गोलीबारी के बाद आरोपी ने मौके से भागते समय एक कार चोरी कर ली थी, जिसके बाद पुलिस ने उसका पीछा किया । पुलिस ने अभी तक आरोपी की पहचान उजागर नहीं की है, लेकिन उसे एक वयस्क पुरुष बताया गया है। प्रारंभिक जांच में इस घटना को घरेलू विवाद का परिणाम बताया गया है। फिलहाल श्रेवपोर्ट पुलिस घटना की विस्तृत जांच कर रही है और गोलीबारी की वजह जानने का प्रयास कर रही है । घटना की भयावहता को बताते हुए पुलिस ने कहा कि ऐसा दुर्घट्य उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था ।एसोसिएटेड प्रेस और यूएसए टुडे द्वारा नॉर्थईस्टर्न यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर बनाए गए डाटाबेस के अनुसार, जनवरी 2024 में शिकागो के उपनगर में हुई घटना के बाद यह अमेरिका की सबसे घातक सामूहिक गोलीबारी है ।

ईरान सेना और विदेश नीति पर आईआरजीसी का नियंत्रण; कमांडर अहमद वाहिदी ले रहे हैं देश के फैसले

तेहरान, एजेंसी। ईरान को लेकर आई एक रिपोर्ट के मुताबिक, अब वहां की सेना और विदेश नीति पर कट्टरपंथी संगठन इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (आईआरजीसी) का पूरा नियंत्रण हो गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आईआरजीसी के कमांडर अहमद वाहिदी और उनके सहयोगी अब देश के फैसले ले रहे हैं, जबकि पहले जो नेता बातचीत और शांति की कोशिश कर रहे थे, उन्हें किनारे कर दिया गया है।

बताया गया है कि अब्बास अराघची जैसे नेता अमेरिका के साथ बातचीत करना चाहते थे और होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने पर सहमत थे, लेकिन आईआरजीसी ने इस फैसले को रोक दिया। इसके बाद ईरान ने उस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों पर हमला भी किया, जिससे कई जहाज फंस गए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अब ईरान के अंदर सख्त रख अपनाया जा रहा है और जो नेता नरम रवैया चाहते हैं, उनकी शक्ति कम हो गई है। इससे अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत मुश्किल हो गई है और क्षेत्र में तनाव बढ़ने का खतरा बना हुआ है।

एशियाई बाजारों में तेजी के साथ कारोबार हो रहा था। टोक्यो, हांगकांग, शंघाई, सोल और जकार्ता हरे निशान में थे। केवल बैंकोंक लाल निशान में था।

ट्रंप के टैरिफ वार से परेशान कनाडा, दुनिया में नए व्यापारिक रास्ते की कर रहा तलाश

ओटावा, एजेंसी। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अमेरिका के साथ बढ़ते व्यापारिक तनाव के बीच देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए नई रणनीति पर जोर दिया है। उन्होंने साफ कहा कि अब सिर्फ अमेरिका पर निर्भर रहना कनाडा की ताकत नहीं, बल्कि कमजोरी बन गया है, और इससे बाहर निकलने के लिए दुनिया के अन्य देशों के साथ व्यापार बढ़ाना जरूरी है। ओटावा से जारी एक वीडियो संदेश में कार्नी ने बताया कि अमेरिका ने अपने व्यापारिक रवैये में बड़ा बदलाव किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में टैरिफ (आयात शुल्क) को इतना बढ़ा दिया गया है, जैसा कि पहले केवल महामंदी के समय देखा गया था। इन भारी शुल्कों का सीधा असर कनाडा के ऑटोमोबाइल, स्टील और लकड़ी (लंबर) उद्योग पर पड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 की शुरुआत से ही अमेरिका ने कनाडा से आने वाले कई उत्पादों पर कड़े टैरिफ लगाए हुए हैं। कुछ सामानों पर 25% तक और स्टील व एल्यूमिनियम पर 50% तक टैक्स लगाया गया है। इससे दोनों देशों के बीच सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित हुई है और कनाडा पर नए व्यापारिक विकल्प तलाशने का दबाव बढ़ गया है। कार्नी ने बताया कि उनकी सरकार पिछले एक साल में चार महाद्वीपों में 20 नए व्यापार समझौते कर चुकी है। अब सरकार का फोकस विदेशी निवेश बढ़ाने, देश के अंदर राज्यों के बीच व्यापार नियम आसान बनाने और स्वच्छ ऊर्जा (क्लीन एनर्जी) क्षमता को दोगुना करने पर है।



संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में इक्विटी में 683.20 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश किया था। वहीं, घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने इक्विटी में 4,721.48 करोड़ रुपए की शुद्ध बिकवाली की थी। अमेरिका-ईरान तनाव के बीच भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत सोमवार को सपाट हुई। सुबह 9:17 पर सेंसेक्स 137.14 अंक या 0.17 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 78,356.40 और निफ्टी 61.65 अंक या 0.25 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,291.50 पर था। बाजार में

गिरावट का नेतृत्व मेटल और रियल्टी तेजी के साथ बंद हुए थे। विदेशी



में निफ्टी मेटल और निफ्टी रियल्टी टॉप लुजर्स थे। इसके अलावा निफ्टी इंडिया डिफेंस, निफ्टी पीएसई, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, निफ्टी कर्मांडिटोज और निफ्टी ऑयल एंड गैस भी लाल निशान में थे। दूसरी तरफ निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी मीडिया और निफ्टी कंजेशन हरे निशान में थे। दूसरी तरफ मिडकैप और स्मॉलकैप में तेजी देखने को मिल रही थी। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 303.70 अंक या 0.51 प्रतिशत की तेजी के साथ 60,201.90 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 38.40 अंक या 0.22

होर्मुज की सुरक्षा पर भारत-दक्षिण कोरिया साथ, राष्ट्रपति ली ने सप्लाई चेन सहयोग बढ़ाने पर दिया जोर

सियोल, एजेंसी। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे यूनग ने कहा है कि दक्षिण कोरिया और भारत को होर्मुज जलडमरूमध्य में सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि वैश्विक सप्लाई चेन को स्थिर बनाने और ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने के लिए दोनों देशों के बीच साझेदारी बेहद अहम है। राष्ट्रपति ली ने एक साक्षात्कार में यह टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रस्तावित शिखर वार्ता से पहले की। यह बैठक उनके राष्ट्रपति पद संभालने के बाद मोदी के साथ तीसरी आमने-सामने की मुलाकात मानी जा रही है।

होर्मुज में आई बाधा का असर पूरे विश्व पर पड़ा: उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से जारी संघर्ष के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर असर पड़ा है। इसके चलते वैश्विक तेल कीमतों में तेजी आई है और औद्योगिक उत्पादन के लिए जरूरी कच्चे माल की आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। राष्ट्रपति ली ने कहा कि दक्षिण कोरिया और भारत

प्रतिशत की मजबूती के साथ 17,604 पर था। सेंसेक्स पैक में ट्रेड, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एशियन पेंट्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, अदाणी पोर्ट्स, एलएंडटी, एक्सिस बैंक, एनटीपीसी, एचयूएल, बजाज फिनसर्व, एमएंडएम, बजाज फिनसर्व, भारती एयरटेल, टाटा स्टील और इंडिगो नेनर्स थे। वहीं, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, कोटक महिंद्रा बैंक, टीसीएस, टाइटन और इटरनल लुजर्स थे। ईरान का परमाणु कार्यक्रम: अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह बंद कर दे, लेकिन तेहरान का कहना है कि किसी भी तरह की पाबंदी केवल सीमित वर्षों के लिए होनी चाहिए। ईरान का यूरेनियम भंडार: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने लगभग 400 किलोग्राम उच्च संबंधित यूरेनियम को अमेरिका को सौंप दे। लेकिन ईरान ने इस मांग को पूरी तरह खारिज कर दिया है। होर्मुज जलडमरूमध्य: ईरान का कहना है कि वह इस समुद्री मार्गों पर अपनी पाबंदियां तब तक बनाए रखेगा, जब तक अमेरिका ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी नहीं हटाता। लेकिन ट्रंप का कहना है कि जब तक समझौता नहीं होता, तब तक यह रोक जारी रहेगी।



दोनों अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए पश्चिम एशिया से आने वाले कच्चे तेल और प्राकृतिक



गैस पर काफी हद तक निर्भर हैं। ऐसे में महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों की सुरक्षा हमारे नागरिकों की सुरक्षा और हमारे देशों के अस्तित्व से जुड़ा मुद्दा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि दक्षिण कोरिया भारत के साथ लगातार संवाद बनाए रखेगा ताकि सभी

महिला पत्रकार के होर्मुज से जुड़े सवाल पर भड़के ट्रंप, कहा- बाहर जाओ; भारत से क्या कनेक्शन?

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं। इस बार मामला भारतीय जहाजों पर हुए हमले से जुड़ा है, जिस पर सवाल पूछने पर वह भड़क गए। दरअसल, व्हाइट हाउस कवर करने वाली ओलिविया रिनाल्डी ने ईरान में चल रही स्थिति और होर्मुज में हाल की घटनाओं को लेकर सवाल पूछने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने भारतीय जहाजों पर हमले का जिक्र किया, ट्रंप नाराज हो गए और उन्होंने पत्रकार को बाहर निकलने को कह दिया। यह घटना ऐसे समय में सामने आई है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। रिपोर्ट के मुताबिक, होर्मुज पार करने की कोशिश कर रहे दो भारतीय जहाजों पर ईरान ने हमला किया था, जिस पर भारत ने भी नाराजगी जताई है। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। एक यूजर ने वह क्लिप शेयर की, जिसमें ट्रंप पत्रकारों को बाहर जाने के लिए कहते नजर आ रहे हैं। जिसके बाद उसी पोस्ट को महिला रिपोर्टर ने खुद भी शेयर करते हुए लिखा, ‘मैंने राष्ट्रपति से होर्मुज में मौजूद दो जहाजों के बारे में पूछने की कोशिश की, जिन पर कथित तौर पर ईरानी गनबोट्स ने गोलियां चलाई थीं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा- बाहर निकलो।’ ओलिविया रिनाल्डी सीबीएस न्यूज में व्हाइट हाउस रिपोर्टर हैं। वह 2024 के राष्ट्रपति चुनाव अभियान की कवरेज भी कर चुकी है। इससे पहले वह सीबीएस इवनिंग न्यूज में एसोसिएट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुकी हैं। इस बीच, ट्रंप ने ईरान को लेकर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि ईरान ने संघर्ष-विराम का गंभीर उल्लंघन किया है, लेकिन उन्हें अब भी शांति समझौते की उम्मीद है। ट्रंप ने कहा, ‘यह होगा। किसी न किसी तरह। अच्छे तरीके से या मुश्किल तरीके से। यह होकर रहेगा।’



जहाज होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित और स्वतंत्र रूप से गुजर सके। साथ ही दोनों देश अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी इस साझा प्रतिबद्धता को मजबूत करेंगे।

महत्वपूर्ण खनिजों पर दिया जोर

ऊर्जा निर्भरता कम करने और आपूर्ति संकट से निपटने के लिए राष्ट्रपति ली ने महत्वपूर्ण खनिजों की सप्लाई चेन में सहयोग बढ़ाने की भी वकालत की। उन्होंने कहा कि पारंपरिक आयात मॉडल से आगे बढ़ते हुए दक्षिण कोरिया की तकनीकी क्षमता और भारत की खनन व रिफाइनिंग क्षमता को जोड़कर स्थिर और भरोसेमंद सप्लाई चेन बनाई जा सकती है। उ केवल पारंपरिक क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि एआई, रक्षा, शिपिंग, शिपबिल्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और वित्तीय सेवाओं जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में भी साझेदारी को नई गति दी जाएगी।

ओमान सागर में टकराव: यूएस ने मालवाहक जहाज को किया जब्त, ईरान ने समुद्री डकैती बताकर दी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी

तेहरान, एजेंसी। ओमान सागर में बढ़ते तनाव के बीच ईरान और अमेरिका के बीच टकराव एक बार फिर खुलकर सामने आ गया है। ईरान ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि अमेरिका ने उसके मालवाहक जहाज तोरका पर हमला कर उसे अपने कब्जे में ले लिया है। तेहरान ने इस कार्रवाई को समुद्री डकैती करार देते हुए कड़ी प्रतिक्रिया देने की चेतावनी दी है। ईरान के सैन्य मुख्यालय हजरत खतम अल-अबिया की ओर से जारी बयान में कहा गया कि अमेरिकी सेना ने ओमान सागर के अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में ईरानी जहाज पर हमला किया। बयान के अनुसार, अमेरिकी मरीन ने जहाज पर चढ़कर उसके नेविगेशन सिस्टम को निष्क्रिय कर दिया और उसे जब्त कर लिया। वहीं, अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड (सेंटकोम) ने इस कार्रवाई को सही ठहराया है। अमेरिका का दावा है कि मालवाहक जहाज अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी का उल्लंघन कर रहा था। सेंटकोम के अनुसार, गाइडेड-मिसाइल डेस्टॉयर स्पूअंस ने जहाज को रोका और कई बार चेतावनी दी। लेकिन जब जहाज के क्रू ने आदेशों का पालन नहीं किया, तो अमेरिकी जहाज ने फायरिंग कर उसके इंजन को निष्क्रिय कर दिया। इसके बाद अमेरिकी मरीन ने जहाज पर चढ़कर उसे अपने कब्जे में ले लिया। अमेरिका ने इस पूरी कार्रवाई को पेशेवर और संतुलित बताया है। उन्होंने यह भी कहा कि जहाज पर अमेरिकी मरीन तैनात हैं और वे अंदर की जांच कर रहे हैं कि उसमें क्या सामग्री मौजूद है। इस जहाज का नाम 'तोर्सका' बताया जा रहा है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि इस जहाज को अमेरिकी नौसेना के गाइडेड मिसाइल डेस्टॉयर ने ओमान की खाड़ी में रोका। इसे रुकने की चेतावनी दी गई लेकिन उसने आदेश नहीं माना।

